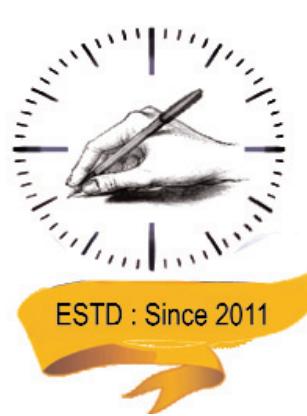




राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समय दर्शन



रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

दर्शन

संस्थापक : स. श्रीमति निलिमा खड़तकर

निष्क्रिय निर्भीक खबरों के साथ

ESTD : Since 2011

संपादकीय

ਵੈਡਿੱਸ਼ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਲੌਟਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਪ

नतीजा वही उभरा, जिसका अनुमान पहले से था। अब डॉनल्ड ट्रंप ह्याइट हाउस में लौटने जा रहे हैं और उसके साथ ही उनसे जड़ी रहीं तमाम अनिश्चितताओं और आशंकाओं की भी वापसी हो गई हैं। जो बाइडेन व कमला हैरिस प्रशासन ने अपने ही कई फैसलों और नीतियों से खुद अपने समर्थन आधार की जड़ें कमज़ोर की थी। दूसरी तरफ डॉनल्ड ट्रंप ने गुजरे चार साल में ट्रॉपिज्म को ना सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि बाइडेन प्रशासन से बढ़े असंतोष को अपने पक्ष में संगठित करने में लगातार जुटे रहे। बाइडेन- हैरिस ने ट्रंप के स्थिलाफ आधे-आधे मन से कानूनी कार्रवाइशं कीं, जिनसे पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों में प्रतिशोध की भवना बढ़ाई। चुनाव अभियान के दौरान दो बार हुए जानलेवा हमलों ने ट्रंप के लिए सहानुभूति और बढ़ा दी। नतीजा चुनाव में लैंडस्लाइड जैसे जनादेश के रूप में सामने आया है। इस लहर पर सवार होकर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस (संसद) में भी निर्णायक जीत हासिल कर ली है। राज्यों के गवर्नरों के चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी रहा। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रबंधक चुनाव नतीजों की ईमानदारी से समीक्षा करें, तो उहें अपनी उन बड़ी गलतियों का अहसास होगा, जिनके कारण उहें इतना बड़ा झटका लगा है। ऊंची उमीदें जगाकर सत्ता में आने के बाद वादों से मुकरना, विदेश नीति में युद्ध को प्राथमिकता बनाना, और इस भरोसे बैठे रहना कि ट्रंप के भय से लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को बोट डालने के लिए विवश बने रहेंगे, पार्टी को भारी पड़ा है। हकीकत यह है कि ट्रॉपिज्म का समर्थन आधार लगातार मजबूत बना हुआ है, जो अब रिपब्लिकन पार्टी की आधिकारिक विचारधारा बन चुका है। इसका मुकाबला पुरानी मध्यमार्गी नीतियों से करने की रणनीति के सफल होने की संभावना आरंभ से ही कमज़ोर थी। ऊपर से बाइडेन की लगातार कमज़ोर होती गई मानसिक क्षमता डेमोक्रेट्स की बड़ी समस्या बन गई। इसके बीच अचानक कमला हैरिस को उमीदवार बनाने का दाव पार्टी ने चला, मगर यह साफ होता गया कि नई उमीदें जगाने का हैरिस के पास कोई एजेंडा नहीं है, जबकि बाइडेन की विरासत से रहा उनका जुड़ाव उहें महंगी पड़ेगा- यह शुरुआत से स्पष्ट था। आखिरकार नतीजा वही उभरा, जिसका अनुमान पहले से था। अब डॉनल्ड ट्रंप ह्याइट हाउस में लौटने जा रहे हैं और उसके साथ ही उनसे जड़ी रहीं तमाम अनिश्चितताओं और आशंकाओं की भी वापसी हो गई हैं।

अमेरिका के साथ भारत के संबंध अब भी अच्छे

एस. सुनील

ट्रूप का एक और भाषण जो भारत में बहुत प्रसारित हुआ उसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। ट्रूप ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वह बर्बर है। दुनिया का कोई नेता, जब बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ तो ट्रूप हुए। क्या यह कोई मामूली बात है? क्या इस पर भारत के लोगों को खुशी नहीं माननी चाहिए?

डोनाल्ड ट्रंप लौट आए हैं। अमेरिका के इतिहास में 131 साल में वे पहले राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने कमबैक किया है। चार साल राष्ट्रपति रहने और फिर बेहद कड़वाहट भरे चुनाव में हार कर सत्ता से बाहर होने के बाद वापसी करके ट्रंप ने दिखाया है कि वे एक योद्धा हैं। उनके ऊपर महाभियोग चला। कई मुकदमे हुए। मुकदमे में सजा हुई। चुनाव प्रचार के दौरान उनके ऊपर गोली चली। लेकिन वे मैदान में ढटे रहे और चुनाव जीता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नतीजों के 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद जब बधाई दी तो उनके साहस और योद्धा वाली भावना की तारीफ की और कहा कि वे ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध पर बात करने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार में कहा था कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद एक घंटे में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप की जीत के बाद पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलदोमीर जेलेंस्की दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि वे युद्ध खत्म कराएंगे। अगर ऐसा होता है तो सोचिए यह दुनिया के लिए कितनी राहत की बात होगी!

दुनिया का हार देश ट्रंप के लौटने को अपने हिसाब से देख रहा है और उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। यूरोप के देशों खास कर फांस और जर्मनी की प्रतिक्रिया सधी हुई लेकिन आशंका वाली थी। ट्रंप के आने के बाद इमेनुएल मेर्कोर्ड और ओलाफ शुल्ज दोनों यूरोपीय संघ की एकजुटता की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की प्रतिक्रिया सामान्य थी लेकिन सबको पता है कि लेबर प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई बड़े प्रशंसक नहीं हैं। चीन के राष्ट्रपति ने तो उनको जीत पर निजी तौर पर बधाई ही नहीं दी। कुल मिला कर दुनिया के दो देश ऐसे हैं, भारत और इजराइल, जिनकी प्रतिक्रिया वास्तविक अर्थों में ट्रंप की जीत पर खुशी और संतोष वाली थी। इसी खुशी और संतोष के अंदर ज में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने %अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप' को बधाई दी। नतीजों के तुरंत बाद उन्होंने बधाई दी और उसके थोड़ी देर बाद दोनों

का बातचात भा हुई, जिसका जानकारा खुद प्रधानमंत्री न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। आश्वर्य नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर आम भारतीय नागरिकों ने भी खुशी मनाई। भारत के लोगों ने उनके भाषणों के वीडियो शेयर किए। उनके दो भाषण सबसे ज्यादा शेयर किए गए। अपने एक भाषण में ट्रंप ने कहा कि, %मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अगर मैं चुनाव जीता तो हिंदुओं का, भारतीयों का एक सच्चा दोस्त व्हाइट हाउस में होगा'। उन्होंने आगे कहा, %भारतीय हिंदुओं की कई पीढ़ियों ने हमारे देश अमेरिका को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है'। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के 256 साल के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने भारत और हिंदुओं के बारे में इतनी सकारात्मक, सार्थक और अच्छी बातें नहीं कही हैं। ट्रंप का एक और भाषण जो भारत में बहुत प्रसारित हुआ उसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वह बर्बर है। दुनिया का कोई नेता, जब बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ तो ट्रंप हुए। क्या यह कोई मामूली बात है? क्या इस पर भारत के लोगों को खुशी नहीं मनाने चाहिए? ट्रंप की जीत पर भारतीयों के खुशी मनाने के एक नहीं कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके निजी सबध बहुत अच्छे हैं।

धीमी न्यायिक प्रक्रिया के विकल्प पर सोचना होगा

उमेश चतुर्वेदी

उलेमा बनाम उत्तरी दिल्ली मामले पर सुनवाई के दौरान जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की थीं, इस मामले पर आए फैसले का अंदेशा उनसे हो गया था। सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इसके लिए मानक प्रक्रिया बनाकर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के हाथ जरूर बांध दिए हैं। जैसा कि हर फैसले के साथ होता है, हर पक्ष अपने-अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के विरोधी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं इसके समर्थक इस फैसले में भी कार्रवाई के लिए राह खोज रहे हैं। इससे साफ है कि बुलडोजर व्याय सिर्फ स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, ब्रेक नहीं बन पाएगा। स्पीड ब्रेकर तेज रफ्तार वाहनों की रफ्तार को धीमी करता है, जबकि ब्रेक गाड़ी को रोक देता है। यह फैसला भी कुछ इसी तरह का साधित होने जा रहा है।



वजह है कि इस फैसले के बाद अपराधियों, गैंगस्टरों, असामाजिक तत्वों के उभार को लेकर समाज का एक बड़ा वर्ग सशक्ति हो उठा है। देश की सबसे बड़ी अदालत होवे के चलते सुप्रीम कोर्ट को इस सामाजिक सौच का भी संज्ञान लेना चाहिए और उसे भी आश्वस्त करना चाहिए कि उसके फैसले के बावजूद किसी गैंगस्टर, कोई अपराधी या समाज विरोधी तत्व को कमज़ोर तबके की जमीनों या सार्वजनिक संपत्तियों के अतिक्रमण का हक नहीं मिल जाता।

सुप्रान काट ज धू फसला उतरा दिल्ली के एक मामले में दिया है। अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीर पुरी में रामनवमी के दिन निकले जुलूस पर एक मस्जिद और उस इलाके से जुलूस पर हुए पथराव और उससे उपजी हिंसा के जवाब में दिल्ली नगर निगम ने अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई को सांप्रदायिक कार्रवाई का रंग देते हुए सेकुलर धारा के दिग्गज वकीलों मसलन कपिल सिंखल आदि ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भले ही सुनवाई इसी मामले की होती रही, लेकिन संदेश ऐसा चाहा गया कि उन्होंने अपने अधिकारी की

सुप्राम काट न बुलडोजर कारवाई का मानक प्रक्रिया बनाते हुए त्वरित व्याय के विकल्प या व्याधिक प्रक्रिया की घुमावदार गलियों को पूरी तरह नजरंदाज किया है। यही गया माना उत्तर प्रदेश का सरकार का बुलडोजर कार्वाई के खिलाफ सुनवाई हो रही है। इसकी वजह यह रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्वरित व्याय के विकल्प के रूप में

अपनाया। तब उत्तर प्रदेश सरकार को जर यह छवि बनाई गई कि वह सिर्फ पसंख्यक यानी मुस्लिम तबकों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करती है। जबकि योगी कार ने बिरादरी से ब्राह्मण लेकिन कर्म से फेंचा और गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ इस कार्रवाई को किया। भद्राही के बिरादरी पंडित गैंगस्टर और राजनेता विजय मिश्रा अतिक्रमित संपत्तियां भी उत्तर प्रदेश कार के निशाने पर रहीं। लेकिन प्रचारित हिंसा अतीक, मुख्तार जैसे मुस्लिम दबंगों और फेंचाओं की संपत्तियों के खिलाफ हुई वाई ही की जाती रहीं। इस बहाने त्वरित ये के इस सरकारी विकल्प को हिंदुत्वावादी नवीनीतिक दर्शन का ना सिर्फ नवीजा बताया, बल्कि यह नैरेटिव स्थापित कर दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुलोंगों के बीच संदेश यही गया है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफआया फैसला है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रचारित सिर्फ योगी सरकार रही, लेकिन अवैध अतिक्रमण के जाफ आंध्र, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये प्रदेश आदि सरकारों ने भी की है। एक कड़े के मुताबिक, पिछले सात सालों में जून 2000 अवैध अतिक्रमण बुलडोजर वाई में ढहाए गए। जिनमें सबसे ज्यादा जून 2000 डेढ़ हजार मामले उत्तर प्रदेश के ही रहे।

ज उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई से खाली
गई जमीनों को कमज़ोर तबकों में बांटा
या है। करीब सात सौ ऐसे प्लॉट बांटे जा
ते हैं। इसकी वर्चा कम हो रही है।

श्रित तौर पर इससे किसी को इनकार होगा कि किसी अपराधी के अपराध की उसका पूरा परिवार अपना घर गवांकर बुकाए। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अधी का घर भी अगर सरकारी तंत्र के ने पर बना तो उसकी वजह उसका मैत निर्माण नहीं, बल्कि अवैध कब्जा और नमण रहा। अब तक बुलडोजर कार्टर्वाई पालिकाओं, पंचायती राज संस्थाओं का रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में स्थानीय जिला अधिकारी और उप अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। अवैध कब्जे अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्टर्वाई अधिकारी की निगरानी में होगी और लिए मान्य प्रक्रिया और नोटिस आदि की अवधि का पूरी तरह निर्वहण किया गया। इस प्रक्रिया की राह में एक बाधा नजर ही है। जिला प्रशासन समय और काम के का बहाना बनाकर ऐसी कार्टर्वाईयों को सकता है। अपराधी, माफिया और जैंगस्टर करते रहेंगे, और धीमी व्यायिक प्रक्रिया लिते वे अपने अपराध को प्रकारांतर से गत करते रहेंगे। इससे त्वरित व्याय या की वैकल्पिक सोच भी कुंद होगी। ऐसे व्याय की उम्मीद भी धुंघली होगी। ऐसे में व्याधिक तत्वों पर लगाम लगा पाना आसान रह जाएगा। बुलडोजर कार्टर्वाई की वाले फैसले के बाद खास नैरेटिव द्वावा मिलेगा। यह धारणा बलवती होगी और यह निर्फलहिंदुत्वादी सरकारें ही बुलडोजर व्याय भरोसा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट तो खुद या के बीच इस छवि के खंडन के लिए जा सकता। इसलिए दूसरे जिम्मेदार तंत्र को देश में प्रयास करना चाहिए। लगे हाथों कोर्ट को व्याय में देरी और उसकी धीमी या को भी नियंत्रित करने की कोशिश चाहिए। ताकि बुलडोजर व्याय की त ही ना पढ़े। अगर व्यायिक प्रक्रिया व्य तरीके से चलती रहे तो शायद ही कोई जो बुलडोजर कार्टर्वाई को ही व्याय का न विकल्प माने।

यदि रूस ने एटमी जंग छेड़ दिया तो अमेरिका व उसके मित्र देशों की तबाही तय है?

कमलेश पांडे

कर देते हैं। उधर, यूक्रेन अपने शत्रु रूस के खिलाफ अमेरिकी मिसाइल के उपयोग के बाद ब्रिटिश (इंग्लैंड) मिसाइल का उपयोग करके रूस को और भड़काने की कोशिश करता है। इससे साफ़ है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की विदेशी यानी नाटो देशों की मदद से रूस को पछाड़ने की पित्तरत से युक्रेनियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जो उनकी सियासी मूर्खता है।

सवाल है कि जब पुतिन ने अपने देश में परमाणु युद्ध से बचाव वाले शेल्टर्स बनवाने शुरू कर दिए हैं तो यह तय भी कर लिया होगा कि जैसे अमेरिका ने जापान के खिलाफ परमाणु बम का प्रयोग करके विश्वशक्ति बन गया, कुछ वैसी ही ताकत यूक्रेन व उसको शह देने वाल देशों को परमाणु सबक सिखलाकर हासिल की जा सकती है। चीन से लेकर उत्तर कोरिया तक और ईरान जैसे देशों की रूस की इस नई रणनीति को मूक समर्थन प्राप्त है। वर्हीं, भारत की तटस्थिता भी रूस के लिए समर्थन जैसा ही है।

दरअसल, कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की

भावनाओं का दराकरान करते हुए यूक्रेन का रूस के भीतर अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी की दी थी। जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुतिन ने एटमी हथियार से जुड़े नए आदेश पर 19 नवम्बर 2024 मंगलवार को ही दस्तखत किए हैं। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में सैनिक उतारे थे, जिसके बाद यूक्रेन जंग के 1000 दिन इसी दिन को पूरे हो चुके हैं।

ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि आखिर पुतिन ने अपनी एटमी नीति क्यों बदली? तो जवाब में रूसी मामलों के जानकारों का कहना है कि पुतिन का मकसद यही है कि यूक्रेन का समर्थन कर रहे देश उस पर हमला न कर सकें। ऐसे खतरों से बचने के लिए ही एटमी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देना एक तरह से पश्चिमी देशों को पीछे हटने को मजबूर करना है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से इंग्लैण्ड ने हाल में ही यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है, जिसके दृष्टिगत अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? अमेरिका ने तो लैंड माइंस भी देने का निर्णय लिया है। इससे रूस आगबबूला हो चुका है। सवाल है कि अमेरिकी मंजूरी के बाद लगे हाथ

गड़करी जी बधाई के पात्र तो है ही?

ओमप्रकाश महेता

आज देश पर राज कर रहा भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश छोटे-बड़े नेता सत्ता के झूले पर प्रसन्न मुद्रा में झूल रहे हैं, वही कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे भी हैं, जिन्हें मौजूदा स्थिति की काफी चिंता है इन नेताओं में से केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने तो अपनी वेदना सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी कर दी, उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की फसल अब जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही है, उसमें कोई लगाने की भी चिंता बनती जा रही है सत्तारूढ़ दल से जुड़े ऐसे स्पष्टवादी नेता आज बहुत कम हैं, सत्तारूढ़ दल के कभी अध्यक्ष रह चुके गडकरी जी की गिनती आज भी मुख्य राजनेताओं में होती है, उनकी स्पष्ट राय है कि १००% इस पर लगे कीड़ों को नष्ट करने के लिए असरकारक कीटनाशक छिड़कने की बहुत तीव्र आवश्यकता है, वर्ना ये कीड़े पूरी फसल को ही नष्ट कर देंगे।” फसल बचाने के लिए यह त्वरित कदम जरूरी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों देश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी में दल बदलकर आने वाले दागी नेताओं कार्यकर्ताओं का भीषण दौर जारी है और भाजपा के तरिष्ठ नेता बिना किसी की भी व्यक्ति जाने

भाजपा के बरिष्ठ नेता बना किसा का भा विगत जान पार्टी में सभी को प्रवेश दे रहे हैं इसी व्यवस्था को इंगित करते हुए गड़करी ने यह चेतावनी पूर्ण बयान जारी किया है, उनका स्पष्ट कथन है कि जैसे-जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है, कुछ समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, ऐसे दौर में पार्टी को अपनी स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने अपने इस कथन को स्पष्टत-उदाहरण के साथ समझाये हुए कहा कि पार्टी को कीटनाशक छिड़कने की जरूरत समझना चाहिए, क्योंकि जब फसल बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं बीजेपी की फसल बहुत बड़ी हो गई है, जिसमें अच्छे अनाज के साथ कुछ बीमारियां भी गा गई हैं, इसलिए अब कीटनाशक का उपयोग जरूरी हो गया है। उन्होंने नए सदस्यों के %पार्टी प्रशिक्षण पर भी जो दिया उनका कहना था कि भाजपा का मुख्य आधार चूंकि पार्टी का कार्यकर्ता ही है इसलिए इस आधार को मजबूर रखने के लिए उसे ठोस बनाकर रखना बेहद जरूरी है, उनका यह भी कहना था कि पार्टी में प्रवेशकर्ताओं की राजनीतिक विगत जानना भी बेहद जरूरी है और उनकी निष्ठा और सियासी चाहत को परखना भी जरूरी है। उन्हें पार्टी में प्रवेश के साथ ही पार्टी का पूरा ज्ञान कराना तथा जरूरी प्रशिक्षण पर भी गड़करी जी ने विशेष जोर दिया। अब भाजपा के बरिष्ठतम नेता नितिन गड़करी जी के ये बयान चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आए हों, किंतु मौजूदा राजनीतिक माहौल में इस खरी सीख का हर जगह अपना महत्व है देश में भाजपा अपना सदस्यता अभियान चला रही है और सदस्यता की स्पर्द्धा में ऐसे लोगों को भी सदस्यता दी जा रही है, जिनकी राजनीतिक विगत परखी नहीं गई है, ये अवसरवादी नेता पार्टी में प्रवेश के बाद अपना कौनसा स्वरूप स्पष्ट करेंगे। यह भी सर्विंग ही है, इसी प्रक्रिया पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गड़करी जी ने चेतावनी भरी सीख जाहिर की है और प्रतीक स्वरूप कृषि कर्म की विसंगतियों का उदाहरण पेश किया है अब पूर्व अध्यक्ष इस चेतावनी भरे बयान को पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है, यह तो भविष्य के गर्भ में है, किंतु यहां यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों में अब ऐसी आत्मधाती चेतावनी देने वाले नेता रहे ही कितने गए हैं?

